

इसे वेबसाईट [www.govtpressmp.nic.in](http://www.govtpressmp.nic.in)  
से भी डाउन लोड किया जा सकता है.



# मध्यप्रदेश राजपत्र

## ( असाधारण )

### प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 125]

भोपाल, शुक्रवार, दिनांक 24 मार्च 2017—चैत्र 3, शक 1939

विधान सभा सचिवालय, मध्यप्रदेश

भोपाल, दिनांक 24 मार्च 2017

क्र. 8387-वि.स.-विधान-2017.—मध्यप्रदेश विधान सभा के प्रक्रिया तथा कार्य संचालन सम्बन्धी नियम 64 के उपबंधों के पालन में, मध्यप्रदेश वेट (संशोधन) विधेयक, 2017 (क्रमांक 10 सन् 2017) जो विधान सभा में दिनांक 24 मार्च 2017 को पुरःस्थापित हुआ है. जनसाधारण की सूचना के लिए प्रकाशित किया जाता है.

अवधेश प्रताप सिंह  
प्रमुख सचिव,  
मध्यप्रदेश विधान सभा.

**मध्यप्रदेश विधेयक**

क्रमांक १० सन् २०१७

**मध्यप्रदेश वेट ( संशोधन ) विधेयक, २०१७****मध्यप्रदेश वेट अधिनियम, २००२ को और संशोधन करने हेतु विधेयक.**

भारत गणराज्य के अड़सठवें वर्ष में मध्यप्रदेश विधान-मंडल द्वारा निम्नलिखित रूप में यह अधिनियमित हो :—

संक्षिप्त नाम तथा  
प्रारंभ.

१. (१) इस अधिनियम का संक्षिप्त नाम मध्यप्रदेश वेट (संशोधन) अधिनियम, २०१७ है.

(२) यह मध्यप्रदेश राजपत्र में इसके प्रकाशन की तारीख से प्रवृत्त होगा.

धारा ३४ का  
संशोधन.

२. मध्यप्रदेश वेट अधिनियम, २००२ (क्रमांक २० सन् २००२) (जो इसमें इसके पश्चात् मूल अधिनियम के नाम से निर्दिष्ट है) की धारा ३४ में, उपधारा (२) में, शब्द “रजिस्ट्रीकृत” का लोप किया जाए.

धारा ४६ का  
संशोधन.

३. मूल अधिनियम की धारा ४६ में,—

(क) उपधारा (८) में,—

(एक) खण्ड (क) में, शब्द “बारह कलैण्डर मास” के स्थान पर, शब्द “चौबीस कलैण्डर मास” स्थापित किए जाएं;

(दो) खण्ड (ख) में, शब्द “अपील बोर्ड, प्रत्येक अपील का निपटारा, अपील फाइल करने की तारीख से दो कलैण्डर वर्ष के भीतर करेगा”, के स्थान पर, शब्द “अपील बोर्ड, अपील फाइल करने की तारीख से एक कलैण्डर वर्ष के भीतर उसका लिखित में आदेश सुनाने का प्रयास करेगा” स्थापित किए जाएं;

(ख) उपधारा (८ ख) का लोप किया जाए;

(ग) उपधारा (९) में, शब्द “बारह कलैण्डर मास” के स्थान पर, शब्द चौबीस कलैण्डर मास” स्थापित किए जाएं.

**उद्देश्यों और कारणों का कथन**

अरजिस्ट्रीकृत व्यापारियों के संबंध में अपास्त किए गए एकपक्षीय आदेश के निपटारे हेतु समय-सीमा का उपबंध करने के लिये तथा अपील बोर्ड के साथ-साथ अपीली प्राधिकारी के समक्ष लंबित अपीलों के निपटारे को सुकर बनाने हेतु मध्यप्रदेश वेट अधिनियम, २००२ (क्रमांक २० सन् २००२) में समुचित संशोधन किए जाना हैं.

२. अतः यह विधेयक प्रस्तुत है.

भोपाल :

दिनांक २३ मार्च, २०१७

जयंत मलैया  
भारसाधक सदस्य.

“संविधान के अनुच्छेद २०७ के अधीन राज्यपाल द्वारा अनुशंसित.”

अवधेश प्रताप सिंह  
प्रमुख सचिव,  
मध्यप्रदेश विधान सभा.